



UP में डजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला आयोजित

चर्चा में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) ने उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम लिमिटेड (UPDESCO) के साथ साझेदारी में लखनऊ में [डजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला](#) का आयोजन किया।

मुख्य बंदि

- कार्यशाला का उद्देश्य:
 - डजिटल इंडिया पहल के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
 - डजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के लिये राज्य IT परियोजनाओं के लिये अवसरों की पहचान करना।
 - संभावित अनुकरण के लिये सफल परियोजनाओं का प्रदर्शन।
 - ज्ञान साझाकरण, वचिारों के आदान-प्रदान और उद्योग साझेदारी को सुवधायक बनाना।
- केंद्ररि क्षेत्र:
 - इस कार्यक्रम में डेटा और डजिटल बुनयादी ढाँचे के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया तथा राज्य से अंरुमि छोर तक डजिटल पहुँच के लिये कनेक्टविटि बढ़ाने का आग्रह किया गया।
 - कार्यशाला में राज्य के अधिकारियों और ई-जलिा प्रबंधकों को एक साथ लाकर सुशासन की दशिा में सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की वशिषिटता पर ज़ोर दिया गया।
 - डजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतरगत राष्ट्रीय पहलों पर चर्चा की गई, जनिमें शामिल हैं:
- डजिलिांकर: डजिलिांकर ड्राइवर लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र और शैक्षणिक अंकतालिकाओं सहति वभिनिन दसुतावेजों के डजिटल संस्करणों तक पहुँच की अनुमति देता है।
 - एंटी लॉकर: एंटी लॉकर एक प्रमुख पहल है जिसे डजिटल दसुतावेजों और प्रमाण-पत्रों के भंडारण, साझाकरण और सत्यापन के लिये एक सुरक्षति, कलाउड-आधारति मंच प्रदान करके संगठनों को सशक्त बनाने के लिये डजिाइन किया गया है।
 - API सेतु: API सेतु कोवडि-19 संक्रमण के भय/जोखमि को संबोधति करता है और लोगों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटने में सहायता करेगा।
 - ओपनफोरज (OpenForge): यह ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों के खुले सहयोगात्मक विकास के लिये भारत सरकार का मंच है। इसका उद्देश्य ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग स्रोत कोड के साझाकरण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देना है।
 - माइस्कीम (myScheme): यह एक राष्ट्रीय मंच है जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं की एक ही स्थान पर खोज और जानकारी उपलब्ध कराना है।
- UMANG: UMANG मोबाइल ऐप एक सर्वसमावेशी एकल, एकीकृत, सुरक्षति, बहु-चैनल, बहुभाषी, बहु-सेवा मोबाइल ऐप है। यह संघ और राज्यों के वभिनिन संगठनों की उच्च-प्रभावी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है।
 - UX4G: इसका उद्देश्य वैयक्तिकृत, दृश्य रूप से आकर्षक, कुशल और सुलभ इंटरफेस प्रदान करके डजिटल सेवाओं को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है।
 - साइबर सुरक्षा और क्षमता नरिमाण जैसे प्रमुख वषियों पर भी चर्चा की गई।
 - राज्य स्तरीय चर्चाओं में CM हेलपलाइन (1076), रजसिटरेशन एवं सटामप महानरििक्षक (IGRS), UIDAI इकोसिस्टम और आधार (Aadhaar) प्रमाणीकरण सेवाएँ शामिल थीं।
- खुली परचिर्चा:
 - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के बीच एक सहयोगात्मक सत्र आयोजति किया गया।
 - सत्र के दौरान ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में प्रमुख चुनौतियों और कार्यान्वयन मुद्दों पर चर्चा की गई।
 - बाधाओं के समाधान तथा परियोजना क्रियान्वयन में सुधार के लिये फीडबैक एवं सुझाव मांगे गए।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD)

- परचिय:
 - NeGD की स्थापना वर्ष 2009 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा डजिटल इंडिया

कॉरपोरेशन के तहत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग के रूप में की गई थी।

■ भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ:

- NeGD देश भर में **ई-गवर्नेंस** परियोजनाओं के प्रबंधन और कार्यान्वयन में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सहयोग प्रदान करता है।
- यह केंद्रीय एवं राज्य मंत्रालयों, विभागों और अन्य सरकारी संगठनों को तकनीकी और सलाहकार सहायता प्रदान करता है।

■ प्रमुख परिचालन क्षेत्र:

- **कार्यक्रम प्रबंधन:** ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।
- **परियोजना विकास:** डिजिटल शासन को बढ़ाने के लिये पहल विकसित करना।
- **प्रौद्योगिकी प्रबंधन:** ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के तकनीकी पहलुओं की देख-रेख करता है।
- **क्षमता निर्माण:** सरकारी संगठनों के भीतर कौशल और क्षमताओं को मजबूत करता है।
- **जागरूकता और संचार:** डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ई-गवर्नेंस पहल को बढ़ावा देना।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/digital-india-state-consultation-workshop-organized-in-up>

